RAJYA SABHA

Wednesday, the 20th December, 1989/
29th *Agrahayana,* 1911 *(Saka)*

The House met at fifteen minutes past twelve of the clock, Sir. Chairman in the Chair.

COPT OF PRESIDENTS ADDRESS— *laid on the Table*

MR. CHAIRMAN: Secretary-Gene-ral to lay a copy of the President's Address on the *Table.*

SECRETARY-GENERAL; Sir, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the President's Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 20th December, 1989.

[Text *of the Address delivered by the President (Shri R. Venkatara*-fflon) in *Hindi]*

माननीय सदस्यगण,

लोक सभा के नौवें आम चुनाव के बाद इस प्रथम अधिवेशन में संसद् के दोनों सदनों को सम्बोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नई लोक सभा के सदस्यों को म बधाई देता हूं।

2. अभी-अभी जो आम चुनाव हुए हैं, उससे भारतीय मतदाताओं की परिपक्वता का परिचय मिला है। जनता ने परिवर्तन के पक्ष में स्पष्ट निर्णय दिया है।

3. सरकार ने एक पखवाड़ा पहले ही कार्यभार सम्भाला है और वह जो विभिन्न नीतिगत पहल करना चाहती है और जिन पर बल देना चाहती है उसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के काम में तत्परता से जुट गई है। मैं इस अभिभाषण में केवल उन्हीं व्यापक समस्याओं का उल्लेख कर रहा हूं जिन्हें सरकार सुलझाना चाहती है।

4. मेरी सरकार जनादेश को पूरा करने क लिए वचनबद्ध है। सरकार, राष्ट्र एवं व्यक्ति की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए कार्य करेगी। सरकार, शासन एवं विकास का ऐसा वैकल्पिक स्वरूप अपनाना चाहती है जो आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय के समाजवादी सिद्धान्त., संघवाद एवं विकेन्द्री-करण, संस्थागत उत्तरदायित्व तथा मानव अधिकारों पर आधारित हो। सरकार एक अन्तर-राज्यीय परिषद् स्थापित करने तथा योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए कदम उठायेगी।

5. मेरी सरकार राष्ट्रीय सामंजस्य और आम सहमति की प्रक्रिया विकसित करके राष्ट्र को अनेक समस्याओं का समाधान करने के लि प्रतिबद्ध है।

6. पंजाब समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। पिछले कुछ वर्षों में, हमने व्यापक हिंसा देखी है। अलगाववाद से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और उग्र-वादियों के सामने झुकने का तो प्रश्न ही नही उठता, किन्तु निःसंदेह इस बात की पूरी जरूरत है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास किया जाए। सरकार राष्ट्रीय सहमति के लिए विभिन्न वर्गों के नेताओं के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करेगी। 17 दिसम्बर, 1989 को हुई सर्वदलीय बैठक में इसकी शुरूआत हो चुकी है। रंगनाथ मिश्र जांच आयोग की रिपोर्ट पर शीघ्र कार्रवाई पूरी की जाएगी।

7. जम्मू और कश्मीर की स्थिति अत्यधिक नाजुक है और इसमे गंभीर समस्याएं जुड़ी हुई हैं। देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता की कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के लोगों का, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में किसी से पीछे नहीं रहे हैं, राष्ट्र की प्रगति और विकास की प्रक्रिया में अपनी उचित भूमिका निभाने में समर्थ बनाया जाएगा। राज्य के लोगों की समस्याओं का शीघ्र और स्थायी समाधान खोज निकालने के लिए गहराई से विचार किया जाएगा।

8. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर हमें तत्काल ध्यान देने की जरूरत है । हम इस क्षेत्र के शीघ्र आर्थिक विकास तथा बातचीत और विचार-विमर्श के जरिए असम रहित इस क्षेत्र की जनजातियों से सम्बद्ध मसलों को हल करने के लिए वचनबद्ध हैं ।

9. हाल के महीनों में, देश को साम्प्रदायिक मसलों से उत्पन्न दंगों और हिंसा का सामना करना पड़ा है । धर्म-निरपेक्ष भारत ही हमारी भावनात्मक एकता और राष्ट्रीय अखण्डता का आधार है । अहिंसा के अग्रदूत, महात्मा गांधी की भूमि पर हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है । समय की मांग है कि मैत्री एवं सद्भाव का वातावरण बनाया जाए ताकि किसी प्रकार की साम्प्रदायिक फूट से बचा जा सके । सरकार राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को बढ़ावा देने के अपने अनवरत प्रयत्नों में लोगों का सहयोग चाहती है । राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् को पुनर्गठित किया जा रहा है और यह राष्ट्रीय हित के मामलों में कारगर पहल और पारस्परिक क्रिया-कलापों के लिए मंच का काम करेगी ।

10. स्वस्थ एवं जीवन्त लोकतंत्र का मुख्य आधार है लोकतंत्रीय संस्थाओं की पवित्रता एवं शक्ति । सरकार उन संस्थाओं की गरिमा और शक्ति को पुनः बहाल करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में कमजोर बना दिया गया है । जनता ही शक्ति का स्रोत है । यह अत्यावश्यक है कि लोगों को स्वयं अपने प्रशासन के बारे में अन्तिम निर्णय लेने का हक हो । मेरी सरकार राष्ट्रीय सहमति से पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति, कार्य और संसाधनो की वास्तविक सुपुर्दगी को बढ़ावा देगी ताकि विकास की प्रक्रिया में जनता की पूरी भागीदारी हो । सरकार राज्यों के सहयोग से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं का इन निकायों में समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी । वास्तव में, इस संपूर्ण प्रक्रिया के अन्तर्गत केन्द्र, राज्य, जिला और पंचायत स्तरों पर शासन व्यवस्था के संघीय ढांचे को मजबूत करना होगा ।

11. स्वच्छ सार्वजनिक जीवन लोकतंत्र का मूल आधार है । पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक जीवन के आदर्शों और मूल्यों में लगातार गिरावट आयी है । उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार के मामलों में कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा । सरकार इस सत्र के दौरान लोकपाल की नियुक्ति के लिए एक विधेयक पेश करेगी, जिसके अधिकार-क्षेत्र में प्रधान मंत्री को भी शामिल किया जायेगा ।

12. मेरी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि एक भागीदार लोकतंत्र को प्रबुद्ध और जानकार मतदाताओं की आवश्यकता होती है । इसका यह भी विश्वास है कि पूरी तरह से जनता के समक्ष सरकार के खुले तौर से काम करने से गलत कार्यों की संभावना बहुत कम रह जाएगी । शासकीय गोपनीयता अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाएगा ताकि लोगों को अधिकाधिक जानकारी मिल सके । दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी ताकि सूचना का निरन्तर प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके । इस सत्र में इस आशय का एक विधेयक पेश किया जायेगा । संविधान के उनसठवें संशोधन को, जिससे नागरिक के जीवन के अधिकार को भारी खतरा पहुंचा है, निरस्त किया जायेगा । डाक विधेयक को, जिससे नागरिक के निजी जीवन के अधिकार में हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई थी, वापस ले लिया जाएगा । इसी प्रकार, जांच आयोग अधिनियम के संशोधन के जरिए जनता और संसद् से महत्वपूर्ण सूचना छिपाने की जो कोशिश की गई थी, उसे कानून की पुस्तक से हटा दिया जाएगा । मेरी सरकार संविधान का संशोधन करके, नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित करेगी ।

13. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सामाजिक और आर्थिक अन्याय के शिकार अभी भी बने हुए हैं । सरकार का प्रमुख उद्देश्य इन्हें आर्थिक

और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना होगा ताकि वे अपना जीवन गरिमा और सम्मान से व्यतीत कर सकें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधान-मण्डल में आरक्षण को 10 वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ाया जायेगा।

14. सरकार मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए समुचित कदम उठायेगी।

15. भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं, विशेष रूप से समान रैंक के लिये समान पेंशन और सेवा-निवृत्ति के बाद रोजगार प्रदान करने सम्बन्धी उनकी मांग पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

16. सरकार इस बात की पूरी गारण्टी देगी कि अल्पसंख्यक निर्भय होकर जीवन व्यतीत करें और राष्ट्र की प्रगति में समान भागीदार बनें।

17. संविधान मे पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा दिया गया है। लेकिन महिलाओं को भेदभाव और अपमान अब भी झेलना पड़ रहा है। मेरी सरकार महिलाओं का समान अवसर प्रदान करने के लिए सभी कदम उठायेगी।

18. राष्ट्र की प्रगति में युवकों की विशेष भूमिका होती है। उनकी विशाल शक्ति को एकजुट करके उसे राष्ट्र-निर्माण के कार्य में लगाना है। वे परिवर्तन के अग्रदूत हैं और उन्हें ही एक नए और न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था की आधार-शिला रखनी है। सरकार ऐसे कदम उठायेगी जिनसे युवाशक्ति का इस्तेमाल करने में मदद मिले ताकि सामाजिक शक्तियों को समाज में परिवर्तन लाने के लिये प्रवर्तित किया जा सके। शिक्षा प्रणाली में इस तरह सुधार किया जायेगा कि इससे नई पीढ़ी की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

19. इस सरकार का यह प्रयास होगा कि राष्ट्रीय विकास के लिये हमारे अन्य प्रयत्नों के साथ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षमताओं का एकीकरण सुनिश्चित किया जाए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि का उत्पादन बढ़ाने और प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए किया जाएगा, ताकि रोजगार के अवसर पैदा किये जा सकें, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके और सबसे निचले स्तर पर लोगों को सामान्यतः लाभ मिल सके।

20. सरकार अपनी अर्थव्यवस्था में उत्पादक रोजगार के अवसरों को बढ़ाने को प्राथमिकता देगी। यह समुचित रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि प्रत्येक नागरिक को काम का अधिकार मिले जिससे वह राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में भाग ले सके।

21. आर्थिक मोर्चे पर स्थिति चिन्ताजनक है। अनियंत्रित सरकारी व्यय और उसके परिणामतः धन की आपूर्ति तथा काले धन में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति की समस्या और भी भयंकर हो गई है। आर्थिक असन्तुलन बजट में भारी घाटे के रूप में दिखाई दिया है। भुगतान-शेष पर काफी दबाव बना हुआ है।

22. सरकार, मुद्रास्फीति के दबावों पर काबू पाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हाल के महीनों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। इससे गरीब तथा साधनहीन लोग और गरीब हो गए हैं। सरकार मुद्रास्फीति की समस्या को सुलझाने के लिये हर सम्भव उपाय करना चाहती है।

23. घाटे की वित्त व्यवस्था अत्यधिक नाजुक स्थिति में पहुंच चुकी है। अनावश्यक सरकारी खर्च को कम करने के उपाय किये जायेंगे। हमारी अर्थ-व्यवस्था में बाह्य और आन्तरिक स्थिरता पुनः लाने के लिए सरकारी खर्च और घाटे पर प्रभावी नियंत्रण अनिवार्य पूर्वापेक्षा है।

24. कई मध्यकालिक कारणों से भुगतान-शेष पर दबाव पड़ा है। आयात की व्यवस्था करके और निर्यात को बढ़ावा देकर बहुत कुछ करने की जरूरत है।

सरकार एक कार्य योजना तैयार करेगी जिसका उद्देश्य हमारी बाह्य अदायगी की स्थिति के असंतुलन को ठीक करना होगा।

25. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से आम आदमी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जायेगा और उस पर कड़ी नजर रखी जायेगी। आम खपत की चीजों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इन उपायों से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ये चीजें समाज के कमजोर वर्गों की पहुंच के अन्दर हों।

26. राष्ट्र अभी भी गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक असमानतायें बढ़ी हैं। विकास का लाभ सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से नहीं मिल पाया है। सरकार इस असंतुलन को ठीक करने तथा विकास के लाभों को समाज के निर्धन वर्गों तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। गरीबों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जायेगा और खासतौर पर सरकार एक समयबद्ध कार्यक्रम चलायेगी जिससे सभी गांवों को पीने का पानी मिल सके।

27. हमारे अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से मानव तथा अन्य संसाधनों का पलायन हुआ है। इस प्रवृत्ति को रोकना होगा। सरकारी निवेश परिव्यय के एक महत्वपूर्ण भाग को ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ मोड़ना होगा। सरकार की नीतियों को गरीबों तथा मजदूरों के लिए बनाना होगा। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि कृषि क्षेत्र के संबंध में व्यापार की शर्तों में सुधार हो तथा किसानों को अपनी उपज के लिए लाभकारी कीमतें मिलें। सरकार सीमांत किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, दस्तकारों और बुनकरों को 10,000 रुपए से कम के ऋणों में राहत देने के लिए समुचित कदम उठाएगी। मेरी सरकार भूमि तथा जल जैसे अन्य प्राकृतिक संसाधनों का न्यायोचित वितरण करने के लिए विद्यमान कानूनों में संशोधन करेगी और खेत जोतने वाले को ही खेत का मालिक बनाएगी। भूमि सुधार संबंधी सभी कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा।

28. मेरी सरकार औद्योगिक विकास को इस प्रकार बढ़ावा देगी कि रोजगार के अवसर अधिकतम बढ़ें। लघु-उद्योगों, कृषि संसाधन उद्योगों तथा ग्रामीण दस्तकारों की दस्तकारी पर आधारित उद्योगों और महिलाओं एवं ग्रामीणों के लिए विशेष रूप से लाभदायक ग्रामीण उद्योगों को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपेगी तथा उन्हें सब प्रकार से मदद देगी। सार्वजनिक क्षेत्र को सुव्यवस्थित किया जाएगा ताकि उत्पादित अतिरिक्त माल को इस प्रकार बढ़ावा जाए कि भावी विस्तार के लिए या विकास कार्यकलापों में उपयोग के लिए उनका पुनः निवेश किया जा सके। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को प्रभावी बनाया जायेगा ताकि उत्पादकता और औद्योगिक शान्ति का वातावरण तैयार किया जा सके।

29. पर्यावरण की अधोगति और इसके फलस्वरूप हमारे प्राकृतिक संसाधन आधार के अपक्षय को रोकने के लिए सरकार राज्य नीति के अन्तर्गत जिन विषयों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी उनमें पर्यावरण का संरक्षण भी शामिल होगा। बायोमास के पुनः सृजन संबंधी कार्यक्रमों पर पूरा जोर दिया जाएगा।

30. मेरी सरकार की विदेश नीति का मूलाधार वे आदर्श और सिद्धान्त हैं जिनसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा मिली थी। यह गुटनिरपेक्षता के प्रति हमारी दृढ़ आस्था के जरिए तथा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, जातीय भेदभाव और सभी प्रकार के आधिपत्य और शोषण के विरुद्ध हमारे संघर्ष द्वारा परिलक्षित हुआ है। तेजी से बदलता हुआ अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण, भारत के लिए चुनौती और अवसर दोनों प्रदान करता है जिससे राष्ट्रीय सहमति को और

अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता सिद्ध होती है ।

31. मेरी सरकार दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने और पुनः सुदृढ़ करने तथा सार्क की संरचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय सहयोग की प्रक्रिया में नये सिरे से गतिशीलता लाने को महत्व देती है । सरकार अपने पड़ोसी देशों के साथ अनसुलझे द्विपक्षीय मसलों को सुलझाने का हर सम्भव प्रयत्न करेगी जो कि हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होगा । सरकार इस क्षेत्र में स्थायित्व, विश्वास और सहयोगात्मक प्रयास के एक नये युग में प्रवेश करने के लिए और आगे प्रयास करेगी । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, श्रीलंका सरकार के साथ पहले ही बातचीत शुरू हो चुकी है ।

32. मेरी सरकार भारत और चीन के बीच सद्भाव एवं सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को जारी रखेगी । आशा है कि सीमा के सवाल को हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप उचित और तर्कसंगत तरीके से सुलझाया जा सकता है ।

33. मेरी सरकार सोवियत संघ के साथ अपनी परम्परागत मैत्री को और मजबूत बनायेगी; संयुक्त राज्य अमरीका के साथ रचनात्मक एवं सहयोगात्मक संबंधों को नई दिशा प्रदान करेगी; और जापान तथा यूरोपीय समुदाय के साथ आर्थिक सहयोग सुदृढ़ करेगी ।

34. मेरी सरकार शांतिपूर्ण पश्चिम एशिया में अपने देश को प्राप्त करने के फिलस्तीनी लोगों के अदेय अधिकारों को स्वीकार करती है । इस दिशा में सरकार का समर्थन और एकजुटता हमेशा उपलब्ध रहेगी । मेरी सरकार का यह भी प्रयास रहेगा कि जातीय पृथग्वासन को समाप्त करने के उद्देश्य से बातचीत शीघ्र शुरू करने के लिए प्रिटोरिया शासन पर दबाव जारी रखा जाए । संयुक्त लोकतांत्रिक और जातीय भेदभाव रहित दक्षिण अफ्रीका का अभ्युदय ही हमारा लक्ष्य है ।

35. माननीय सदस्यगण, वर्तमान सत्र थोड़े समय के लिये है । लेकिन यह अपने महत्व की दृष्टि से ऐतिहासिक है और नौवीं लोक सभा के गठन के तुरंत बाद बुलाया गया है, ताकि संसद् के समक्ष नई कार्यसूची प्रस्तुत की जा सके ।

36. मैं आपके प्रयासों की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं ।

जय हिन्द

[Text of the Address delivered by the President in English]

Honourable Members

It gives me great pleasure to address both Houses of Parliament at thig first session after the Ninth GeneraJ- Election *'to* the House of the People. I extend my felicitations to the members of the new Lok Sabha.

2. The General Election, just concluded, has demonstrated the maturity of the Indian electorate. The people have given a clear verdict to favour of change.

3. The Government took charge just a fortnight ago and has commenced in right earnest the task of working out the details of various policy initiatives and thrusts which it intends to adopt. In this Address I am confining myself to the broad issues that the Government proposes to tackle.

4. My Government pledges itself to fulfil the mandate given to it by the people. The Government will work to restore the dignity of the nation and of the inividual. The Government proposes to adopt an alternative model of governance and development based on socialist ideals of. economic equality and social jus tice federalism and decentralisation, institutional (accountability and hu man rights. Government will take

steps to establish an Inter-State Council and to accord constitutional status to the Planning Commission.

5. My Government is committed to a process of national reconciliation and the evolution of consensug to solve the many problems taring the nation,

6. The Punjab problem has defied solution so far. Over the Past few years, we have witnessed widespread violence. There will be no compromise with separatism and no yielding to extremists, but there is admittedly a compelling need for a national endeavour to resolve the problem. The Government will hold wide ranging discussions with leaders of cross-sections of the people to evolve a national consensus. A beginning has already been made in the All Party Meeting held on 17th December, 1989. Action on the report of the Ranganath Misra Commission of Enquiry will be expeditiously completed.

7. The situation in Jammu and Kashmir is extremely delicate and fraught with serious implications. There will be no compromise on the country's unity, sovereignty and integrity. The people of Jammu and Kashmir, who have been second to none in the nation's freedom struggle, will be enabled to play their rightful role in the process of national growth and development. The problems of the people of the state will be gone into in depth with, a view to finding speedy and durable solutions.

8. The North East region requires our immediate attention. We are committed to the speedy economic development of the region and for the settlement of the issues which concern the tribal peoples in the region, including Assam, through dialogue and discussion.

9. In recent months, the country has witnessed riots and violence arising from sectarian issues. A secular India is the very basis of our emotional unity and national - integrity. Violence has no place in the land of Mahatma Gandhi, the apostle of non-violence. The need of the hour is the generation, of an atmosphere of amity and goodwill in order to avoid any communal divide. Government seeks the support of the people in its unrelenting efforts to promote national unity and integrity. The National Integration Council is being reconstituted and will function as a forum for effective initiatives and interaction on issues of national concern.

10. A healthy and vibrant democracy hinges crucially on the sanctity and. strength of democratic institutions. The Government is fully committed to the restoration of the dignity and vitality of institutions which have been weakened in recent years. Power flows from the people. It is imperative that the people themselves should have the final say in governing themselves. My Government will promote on the basis of national consensus a genuine devolution of powers, functions and resources to Panchayati Raj institutions enabling the fullest participation of the people in the developmental process. It will secure, with the cooperation of the states, adequate representation in these bodies for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and women. Indeed the whole process will be one of strengthening the federal structure of the polity at the Centre, the State, the District and the Panchayat levels.

11. A clean public life is the bedrock of democracy. Over the Past few years, there has been a growing erosion of norms and values in public life. The law will take its own course in respect of matters of corruption in high places. The Government will introduce legislation during this session for setting up a Lok Pal, whose jurisdiction will include the Prime Minister also.

12. My Government firmly believes that a participative democracy requires an enlightened and informed electorate. It also believes that an open Government functioning in full public view, will minimise the possibility of wrong doing. The Official Secreta Act will be suitably amended so that people have increased access to information. Doordarshan and AIR will be given autonomy to ensure free flow of information. A bill to this effect will be introduced in this session. The 59th Amendment to the Constitution which seriously jeopardised the citizen's right to life win he repealed. The Postal Bill which Bought to interfere with the citizen's right to privacy will be withdrawn. Similarly, the amendments to the Commissions of Inquiry Act which sought to permit withholding of vital information from the people and Parliament will be removed from the Statute book. My Government will, by amending the Constitution, ensure the citizen's right to information.

13. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes continue to be victims of social and economic injustice. Government's primary aim will be to ensure economic and social justice to them so that they can lead their lives with dignity and honour. The reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the legislatures will be extended by a further period of 10 years.

14. Government will take appropriate steps to implement the recommendations of the Mandal Commission.

15. The problems of ex-servicemen will receive full consideration particularly in regard to their demand for orie-rank-one-pension and their post-retirement employment.

10. The Government will spare no efforts to guarantee that minorities live without fear and as equal partners in the country's progress.

17. The Constitution provides equal status to men and women. Howeverv women continue to suffer from discrimination and indignity. My Government will take all steps to provide equal apprortunities for women.

18. The youth have a special role to play in the progress; of the country. Their vast energies have to be tapped and channelled for the task of nation building. They are the harbingers of change and it is they who have to lay the foundations of a new and just social order. Government will take steps to facilitate the harnessing of youth power for unleashing social forces to transform society. The educational system will be reformed s° that it responds to. the needs and aspirations of the new generation.

19. It will he the endeavour of this Government to ensure integration of the scientific and technological capabilities with our other efforts for national development. Science and Technology will be used for increasing agricultural production, developing technologies that would lead to employment generation, for the proper utilisation of natural resources, and for generally benefitting the population at the grassroots level.

20. Government win give priority to the expansion of productive employment opportunities in the economy. It will strive to ensure appropriately to all citizens the right to work, to enable them to participate in the nation building process.

21. There are disquieting trends of the economic front. Unbridled government expenditure and consequent increase in money supply and proliferation of black money have stoked the fires of inflation. The fiscal imbalance has shown up in the form of a huge budgetary deficit. The balance of payments is under severe strain.

22. The Government attaches the highest priority to curbing inflationary pressures. In recent months, prices of many essential commodities have

risen sharply. This has further impoverished the poor and the under-privileged. Government intends to tackle the problem of inflation in all possible ways.

23. Deficit financing has reached staggering levels. Steps will be taken to reduce wasteful government expenditure. Effective control over Government spending and deficit is an essential pre-requisite for restoring external and internal stability to our economy.

24. A number of medium-term factors have placed a strain on the balance of payments. Much more needs to be done by way of import management and export growth. The Government will formulate an Action Plan which will aim at correcting the imbalance in our external payments position.

25. The rise in prices of essential commodities has affected the common man adversely. The public distribution system will be strengthened and closely monitored. Production of articles of common consumption will be encouraged. These steps will ensure that such commodities are within the reach of the vulnerable sections of the society,

26. Poverty and unemployment continue to confront the nation. Economic disparities have increased in the past few years. All sections of the people have not shared equally the fruits of growth. Government is committed to redress this imbalance and redirect the benefits of development to the poorer sections of society. The Minimum Needs Programme, aimed at the poor will be strengthened and in particular, Government will undertake a time-bound programme to provide all villages with potable drinking water.

27.. The vast majority of our population live in the villages. There has been a flight of resources—both human and otherwise, from our rural areas. This trend has to be stopped. A substantial portion of Government's investment outlay has to be channelled to rural areas. Government's policies will he designed for the poor and the toiling masses. The Government will take steps to see that the terms of trade for the agriculture sector are improved and our farmers receive remunerative prices for their produce. Government will take appropriate steps to provide debt relief for marginal farmers, landless agri-cultural labourers, artisans, and weavers on loans below Rs. 10,000. My Government will revise the existing laws to bring about equitable distribution of land and other natural resources like water and make the tiller of the land its owner. All land reform laws will be incuded in the Ninth Schedule of the Constitution.

28. My Government will promote industrial development in such a Way as-to maximise employment. An important role will be assigned—and all support given—to small-scale industries, to agro processing industries and industries based on the craft of rural artisans as also village industries of particular benefit to women and rural households. The Public Sector will be streamlined so as to augment the surpluses generated so that they Can be ploughed back for future expansion or utilisation* for developmental activities. Labour participation in management will be made effective to promote an environment of productivity and industrial peace.

29. In order to prevent the degradation of the environment and consequent erosion of our natural resource base, Government will make preservation of environment a priority area of State Policy. Programmes for regeneration of biomass will receive fullest- emphasis.

30. My Government's foreign policy is deeply rooted in the ideals and principles which inspired the freedom struggle. This is reflected in its firm adherence to non-alignment and our struggle against imperialism, colonialism, neo-colonialism, racial discrimination and all forms of domination and exploitation. The rapidly changing international environment present both challenges and opportunities for India, underlinking; the need for further strengthening the national consensus.

31. My Government attaches importance to revitalising and strengthening ties with our neighbours in South- Asia, and to imparting fresh dynamism to the process of regional cooperation within the framework of SAARC. The Government will spare no effort to resolve outstanding bilateral issues with our neighbouring countries, consistent with our national interests. The Government will further endeavour to usher in an era of stability confidence and cooperative endeavour in our region. In the pursuit of this objective talks have already been initiated with the Government of Sri Lanka.

32. The process of further understanding and cooperation between India and China will be continued by my Government. It is hoped that the boundary question can be resolved in a fair, reasonable manner in consonance with our national interests.

33. My Government will further strengthen the traditional friendship with the Soviet Union; build upon, the new trends of a constructive and cooperative relationship with the United States; and strengthen economic cooperation with Japan and the European Community.

34. My Government rcognises the inalienable rights of the Palestinian people to achieve a homeland of their own in a peaceful. West Asia. The Government's support and solidarity to this end will always, be there. It will also be my Government's endeavour to maintain pressure on the Pretoria regime to commence early negotiations for the dismantlement of Apartheid. The emergence of a united democratic and non-racial South Africa is our objective.

33. Honourable Members, the present session is a short one. Yet it is' historic in its importance and is summoned immediately following the constitution of the Ninth Lok Sabha in order to place before Parliament the new agenda of work.

36. I wish you all success in your endeavours.

JAI HIND

OBITUARY REFERENCES

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I refer with profound sorrow to the passing away of Shri M. Sherkhan, Shri Shyam Lal Gupta, Shri Shiva Chandra Jha and Shri Abhimanyu Rath, former Members of this House.

Shri M. Sherkhan was born in December 1922 at village Mulkhed of district Gulbarga in . Karnataka State and had his education at Hyderabad. Shri Sherkhang field of in-terest was the welfare and uplift of the labour, minorities and other weaker sections of the society. • He also took keen interest in the cooperative movement. Shri Sherkhan represented the Karnataka State in this House from 1961 to 1972. Later be served as a Member of the Legislative Assemby of Karnataka from 1978 to 1983-.

Shri Shyam Lal Gupta was a Member of this House from the State of Bihar from 1972 to 1979. Shri Gupta was born at Delhi in November 1912, and also had his education in Delhi. Shri Gupta was attracted towards the freedom 'movement of the country at an early age and was arrested for taking part in the Salt Satyagraha and the , Quit India